Sir, the situation is somewhat alarming, and intervention of the Central Government is absolutely necessary for providing relief and rehabilitation to the drought-affected people of the State. Short-term measures for providing immediate relief and long-term measures like providing irrigation facilities, borewells, etc., have to be given top priority to prevent such situations in future.

I, therefore, appeal to the Central Government, through you, Sir, to come to the rescue of the State Government and the affected people of Nagaland which will go a long way in tiding over the current situation in the State.

Demand to provide additional stipend to trainee doctors in entire country, particularly Tamil Nadu

SHRI N.R. GOVINDARAJAR (Tamil Nadu): Sir, I would like to request the Central Government to provide additional stipend to the trainee doctors since the stipend provided by some State Governments is meagre. In Tamil Nadu, the provision of stipend for trainee doctors is so meagre that last week it resulted in a serious situation when trainee doctors went on an indefinite hunger strike unto death. In general, engineering courses with lesser capitation fee and time period for the completion of the course, and good employment opportunities with higher salary are treated as profit-oriented professional courses. But medical graduation has five-and-a-half years of duration with unimaginable capitation fee and additional education expenditure. It is also treated as a life-saving professional course with the motto of 'serving the society without any parity' So, it is the duty of the Government to give more importance to medical students. Presently, the stipend provided in some States, especially Tamil Nadu, is not adequate in comparison to the huge expenditure, duration of course and the never-ending service. Last week, this provision of low stipend forced the trainee doctors to undertake indefinite hunger strike unto death. Many hospitals in- Tamil Nadu were running without trainee doctors, especially the outpatients in Government hospitals were facing severe difficulty due to this strike. So, I urge the Government that it is its duty to consider to provide additional stipend in addition to the State Governments', keeping in view the service of the doctors who studied medical courses by spending a huge amount of money and longer duration.

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI A. ELAVARASAN (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Demand for strict regulations to control the confusing publications brought out by private publishers for children

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आपकी विशेष अनुमति से इस विषय को सदन में उठाना चाहता हूं। देश में प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें बच्चों में भ्रम पैदा करने के साथ-साथ वर्णमाला के ज्ञान की जगह उनके बालमन को सिनेमा की ओर धकेल रही है। उक्त वर्णमाला में "ऋ" से ऋषि की जगह ऋतिक रोशन और "ऐ" से ऐनक की जगह ऐश्वर्या राय पढ़ाया जा रहा है तथा उनका चित्र भी उक्त पुस्तक की वर्णमाला के क्रम में प्रकाशित है। प्रकाशकों की लापरवाही यही नही रुकती है बल्कि महान वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस की

जन्मतिथि को लेकर भी भ्रम पैदा कर रही है। एक प्रकाशक द्वारा 2004-05 के संस्करण में उनकी जन्मतिथि 30 नवम्बर 1858 तथा 2008-09 के संस्करण में 13 नवम्बर 1858 दर्शायी गयी है। छात्र किस जन्मतिथि को सही मानें?

केन्द्रीय मान्यता प्राप्त और राज्य सरकारों की मान्यता के अधीन संचालित विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तकों की कमी का बहाना बनाकर प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें स्कूल में पढ़ायी जाती हैं और अभिभावकों का शोषण किया जाता है।

मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उसके ऊपर प्रभावी निगरानी रखी जाए तथा शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रकाशकों को दंडित किया जाए।

Demand to Amend Section 304-A of Indian Penal Code in view of various tragedies caused due to negligence

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : महोदय, उपहार सिनेमा हाल त्रासदी पीड़ित संघ ने गत शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2009 को राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह मांग की गई है कि अगर कोई आदमी अपने कार्य से बहुत से आदमियों के जीवन को खतरे में डालता है तो इस तरह के अपराध की जांच और न्यायालिक कार्यवाही के लिए एक नया कानून होना चाहिए। यह ज्ञापन उन घटनाओं को मद्देनजर रख कर दिया गया है जिसमें मनुष्य ने अपने लालच और लापरवाही से हजारों लोगों की जान ली। भोपाल गैस त्रासदी में 1000 लोगों की जानें गयी, हरियाणा डबवाली में 452 आग की लपटों में झुलस कर मर गए, उपहार सिनेमा त्रासदी में 59 लोगों ने जानें गवायीं, प्राइमरी के 90 बच्चे कुम्भकोणम में आग की लपटों में समा गए और मेरठ के विक्टोरिया पार्क के मेले में 59 आदमी मर गए। ये सभी घटनाएं मैनमेड हैं, मनुष्य की गलतियों का नतीजा हैं। इन त्रासदियों से हमने कुछ नहीं सीखा और सब कुछ ज्यों का त्यों चल रहा है। इन घटनाओं के जिम्मेदार रहे कितने व्यक्तियों को सजा मिली? इस समय के कानून के अनुसार इस तरह के जुर्म करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-क के तहत मुकदमा चलाया जाता है जो लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर लगता है। यह कानून व्यवस्था का मजाक है कि जिस व्यक्ति ने अपना पैसा बचाने और लालच के चलते सैकड़ों आदमियों की जान ली, उस पर सिर्फ लापरवाही का मुकदमा हो जिसकी सजा सिर्फ दो साल है। 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता में इस तरह के अपराधों का कोई प्रावधान नहीं है। 304-क एक साधारण प्रावधान है जो कहीं भी लगा दिया जाता है। आवश्यकता है कि हम इस colonial कानून से बाहर आकर सोचें और इस विषय पर एक सख्त कानून बनाएं। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में उचित कदम उठाए और आवश्यक कार्यवाही करे।

Concern over widespread poverty and malnutrition in the country

DR. JANARDHAN WAGHMARE (Maharashtra): Sir, India aspires to be an economic world power. Despite recession and meltdown, our economy is not threatened. The Economic Survey 2008-09 paints a very rosy picture of India. But, the other side is dismal and dark. We have 260 million under-nourished people in India. They constitute 27 per cent of the world's under-nourished. About 46 per cent children under three years suffer from malnutrition. Hunger and disease are our greatest enemies.

What is the root cause of this malady? It is, of course, poverty and inequality. Poverty and inequality have been our age-old curse. They are responsible, by and large, for malnutrition,